भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2538

उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना

†2538. श्री इटेला राजेंदरः

श्री राजा राम सिंहः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हाल ही में केंद्रीय बजट प्रस्ताव में प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना के तहत आगामी पांच वर्षों के दौरान विशेष रूप से आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप की दी गई गारंटी है राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और इस प्रयोजन के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है;

(घ) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञान और मानविकी अनुसंधान को उक्त योजना के तहत शामिल किया जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार की केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विशेषकर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए इसी प्रकार की अध्येतावृत्ति योजना शुरू करने की मंशा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार द्वारा देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए वित्तपोषण अंतर का आकलन करने के लिए कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (छ): बजट घोषणा **2018-19** के अनुसरण में**,** सरकार ने **1650.00** करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना (पीएमआरएफ) को अनुमोदन प्रदान किया था। इस योजना का उद्देश्य भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ी हुई वित्तीय

सहायता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले शोध को आगे बढ़ाने के लिए सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकृष्ट करना था। पीएमआरएफ के पहले चरण के तहत, **3688** विद्वानों को प्रवेश दिया गया है। पीएमआरएफ के पहले चरण से अनुसंधान के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और तकनीकी अनुसंधान के लिए बजट 2025-26 में बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ इस प्रकार पीएमआरएफ के तहत 10,000 फैलोशिप की घोषणा की गई है।

अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) अधिनियम, **2023** एएनआरएफ को गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च-स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

*****